

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

सूचना

16 अगस्त 1984

इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान नियमावली, 1984

सं० 490(1)-स्वा०-उप-धारा (1) के परन्तुक के साथ पठित इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अध्यादेश, 1983 (23, 1983) की धारा 26 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल इसके द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान नियमावली, 1984 कहलाएगी।

(2) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं--जब तक संदर्भ में अन्यथा अर्थित न हो, इस नियमावली में --

- (क) "अध्यादेश" से अभिप्रेत है इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अध्यादेश, 1983 (23, 1983) ;
 (ख) "निदेशक" से अभिप्रेत है संस्थान का निदेशक ;
 (ग) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार-राज्य सरकार ;
 (घ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है शासक बोर्ड का अध्यक्ष ; और
 (ङ) "धारा" से अभिप्रेत है अध्यादेश की धारा।

3. शासक-बोर्ड के सदस्यों का नाम-निर्देशन--(क) इंडियन मेडिकल एसोसियेशन द्वारा नाम-निर्देशन-- धारा 5 की मद (6) के अधीन सदस्यों के नाम-निर्देशन के प्रयोजनार्थ, इंडियन मेडिकल एसोसियेशन के अध्यक्ष से उक्त एसोसियेशन की कार्यकारी परिषद् की सिफारिश पर विशिष्ट-व्यक्ति से एक व्यक्ति का नाम-निर्देशित करेंगे।

(ख) धारा 5 की मद (8) के अधीन सदस्य के नाम-निर्देशन के प्रयोजनार्थ, सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के वरीयतम प्रधानाचार्य का नाम निर्देशन करेगा।

(ग) धारा 5 की मद (9) के अधीन सदस्यों के नाम-निर्देशन के प्रयोजनार्थ भारत सरकार (स्वास्थ्य मंत्रालय) चक्रानुक्रम से अ०मा० आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली/स्नातकोत्तर संस्थान (पी०जी०सी०), चंडीगढ़ के निदेशक/संकायाध्यक्ष का नाम निर्देशित करेगी।

(घ) धारा 5 की मद (2) के अधीन सदस्यों के नाम-निर्देशन के प्रयोजनार्थ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष शासक बोर्ड में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक प्रतिनिधि का नाम निर्देशित करेंगे।

(ङ) धारा 5 की मद (12) के अधीन सदस्य के नाम-निर्देशन के प्रयोजनार्थ, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय, शासक-बोर्ड में एक व्यक्ति का नाम निर्देशन करेंगे।

(च) धारा 5 की मद (13) के अधीन सदस्य के नाम-निर्देशन के प्रयोजनार्थ, मेडिकल कांसिल ऑफ इंडिया एक व्यक्ति का नाम निर्देशित करेंगी।

(छ) धारा 5 की मद (14) के अधीन सदस्य के नाम-निर्देशन के प्रयोजनार्थ, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली शासक बोर्ड में एक व्यक्ति का नाम निर्देशित करेंगे।

(ज) धारा 5 की मद (15) के अधीन सदस्य के नाम निर्देशन के प्रयोजनार्थ, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी की परिषद् से शासक-बोर्ड में एक व्यक्ति को नाम-निर्देशित करने का प्रस्ताव की जायेगी।

(झ) धारा 5 की मद (16) के अधीन सदस्य के नाम-निर्देशन के प्रयोजनार्थ, बिहार सरकार का परिवार-कल्याण विभाग शासक-बोर्ड में एक लघु प्रतिष्ठ प्रबंध विशेषज्ञ का नाम निर्देशित करेगा।

निम्नलिखित मांगले स्थायी वित्त शक्ति को निर्दिष्ट किए जायेंगे जो उनपर विचार करके उनके बारे में अपनी सिफारिशें करेंगी :--

- (क) वार्षिक लेखा, जिसमें संस्थान की आय-व्यय दिखाया जाएगा और उसपर दो गई अंकीय रिपोर्ट;
- (ख) वार्षिक प्रगति, जिसमें संस्थान का प्रायकलित आय-व्यय दिखाया जाएगा;
- (ग) नए पदों के सृजन के लिए सभी प्रस्ताव;
- (घ) निदेशक को प्रत्यायोजित मामलों से मित्र संस्थान से संबंधित सभी वित्तीय मामलों;
- (ङ) पदाधिकारियों/उप-समितियों की शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित सभी मामलों;
- (च) निरिद्धा मांगने और उसकी मंजूरी से संबंधित सभी मांगले।

(ग) स्थायी संपदा (इस्टेट) समिति—

यह समिति निम्नलिखित रूप में गठित होगी :--

- (1) संस्थान का निदेशक;
- (2) संस्थान का संकायाध्यक्ष (डीन);
- (3) अस्पताल का चिकित्सा अधीक्षक;
- (4) स्वास्थ्य विभाग (राज्य सरकार) का एक प्रतिनिधि;
- (5) संस्थान का अधीक्षण अभियन्ता;
- (6) लोक निर्माण विभाग का अधीक्षण अभियन्ता;
- (7) विद्युत् विभाग का अधीक्षण अभियन्ता;
- (8) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का अधीक्षण अभियन्ता; और
- (9) धारा 5 की मद (16) के अधीन शासक-बोर्ड में नाम निर्देशित किया जानेवाला एक प्रबंध विशेषज्ञ।

यह समिति संस्थान के भवन के परिवर्द्धन और परिवर्तन पर विचार करेगी और उसके अनुरोध और उपयोग से संबंधित प्रश्नों के संबंध में कार्रवाई करेगी।

(घ) स्थायी अस्पताल समिति—

यह समिति निम्न रूप में गठित होगी—

- (1) संस्थान का निदेशक;
- (2) संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक;
- (3) एक-एक वर्ष के लिए, चक्रानुक्रम से नैदानिक (क्लिनिकल) सेवाओं के पांच विभागाध्यक्ष;
- (4) उस क्षेत्र के निवासियों की प्रत्येक कोटि से एक प्रतिनिधि;
- (5) चिकित्सा अधीक्षक द्वारा नाम निर्देशित की जानेवाली नर्स और सहायक स्टाफ;
- (6) संस्थान का वित्तीय सलाहकार; और
- (7) संस्थान का अधीक्षक अभियन्ता। स्थायी अस्पताल समिति अस्पताल सेवा को और विकसित करने और उसका उच्च स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी।

(ङ) स्थायी चयन समिति—

यह समिति निम्न रूप में गठित होगी :--

- (1) संस्थान का निदेशक;
- (2) बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का सचिव अथवा उसका नाम निर्देशित;
- (3) महानिदेशक/अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, भारत सरकार;
- (4) संस्थान का डीन;
- (5) कार्यकारी परिषद् द्वारा नाम निर्देशित दो विशेषज्ञ; और
- (6) संबद्ध विभागाध्यक्ष, जो समिति में सह-प्राचार्या (एसोसिएट प्रो०) और उसके नीचे के पदों पर चयन के लिए रहेंगे। संस्थान का निदेशक समिति का संयोजक होगा।

(2) स्थायी चयन समिति संस्थान के श्रेणी 1 और 2 के पदाधिकारियों की नियुक्ति और प्रोन्नति से संबंधित सभी विषयों के संबंध में संस्थान से अनुशंसा करेगी।

(3) संस्थान का निदेशक, स्थापना समिति, जिसमें निदेशक, अस्पताल का चिकित्सा अधीक्षक और बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग का एक प्रतिनिधि रहेंगे की अनुशंसा पर श्रेणी 3 और श्रेणी 4 कोटि के सभी मंजूर पदों पर नियुक्ति के लिए, सक्षम होगा।

7. पदों का सृजन और उनपर नियुक्ति-- (क) संस्थान बजट में विनिश्चित उपबंध को अध्याधीन सरकार द्वारा यथा अनुमोदित वेतनमानों में पदों का सृजन कर सकेगी, उन्हें कोटियों में वर्गीकृत कर सकेगी और उनके पदनाम विनिश्चित कर सकेगी।

(ख) संस्थान का निदेशक धारा 12 के अधीन निर्धारित प्रक्रिया को अनुसार नियुक्त किया जायगा।

(ग) संस्थान के सभी पद व्यवसाय संबंधी (नन-प्रैक्टिसिंग) होंगे और घन खुले विज्ञापन के माध्यमों के आधार पर किया जायगा।

8. बजट प्राकल्पन-- वार्षिक बजट जिसमें संस्थान का प्राकल्पित आय-व्यय दिया रहेगा, तीन मासों में सरकार द्वारा विनिश्चित फारम में तैयार किया जायगा और उसके पास प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर तक तीन प्रतिशत में उपस्थापित किया जायगा।

भाग 1-- नैदानिक (मिलनिकल) सेवा केंद्र।

भाग 2-- नैदानिक (मिलनिकल) शोध केंद्र।

भाग 3-- सामुदायिक शोध केंद्र।

9. निधि में निक्षेप और उससे निकासी-- (क) निधि में आकलित सभी धन पटना स्थित भारतीय स्टेट बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी शाखा में जमा किया जायगा।

(ख) निधि निदेशक या इस निमित्त निदेशक द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत संस्थान के किसी पदाधिकारी और संस्थान के वित्तीय सलाहकार के संयुक्त हस्ताक्षर से परिचालित की जायगी और निधि से निकासी चेक द्वारा की जायगी।

(ग) भुगतान के पहले सभी बिलों की जांच संस्था के लेखा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।

10. लेखा का वार्षिक विवरण-- संस्थान के लेखा का वार्षिक विवरण जिसमें सतत-पत्र भी शामिल है सरकार द्वारा निर्धारित फारमों में तैयार किया जायगा। 31 मार्च को समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष से संबंधित विवरण तथा उसकी प्रकृति रिपोर्ट अगले 31 दिसम्बर तक सरकार को भेजी जाएगी और उसके साथ इतनी अतिरिक्त प्रतियां भी रहेंगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा अपेक्षित हों।

11. वार्षिक रिपोर्ट-- धारा 21 में विनिश्चित वार्षिक रिपोर्ट 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से संबंधित होगी और सरकार के अगले 31 अक्टूबर तक अतिरिक्त प्रतियां के साथ भेजी जायगी।

12. विवरणी-- संस्थान सरकार को ऐसे फारम में और ऐसी रीति से विवरणियां और जानकारी भेजेगा जैसा कि सरकार द्वारा अपेक्षा की जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
आर० एन० चौधरी उप-सचिव,

अधीक्षक राजकीय संलग्न सामग्री, मंडार एन प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित तथा

अधीक्षक सचिवालय, गुप्तपालक, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।

बिहार गजट, 17 जुलाई 1984--781--1,000--ग० ना० सहाय।